देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरूवार 22.05.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में 26 हजार करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
- प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों के 86 जिलों के 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया।
- एक राष्ट्र, एक चुनाव पर केंद्र स्तर पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए।
- उत्तरकाशी जिले में अपर यमुना वन प्रभाग की विभिन्न रेंजों में गठित वन पंचायतों के लिए अब पीरूल आय का जरिया बनेगा।

प्रधानमंत्री विकास परियोजनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही 18 राज्यों के 86 जिलों के 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सड़कें, एयरपोर्ट, रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हों, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेलवे के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार किए हैं।

मध्याह्न भोजन

देहरादून ज़िले में स्कूलों में मिड–डे मील यानी मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिये अलग से रसोई होनी चाहिए। जिले के 125 स्कूल ऐसे हैं, जहां आज भी रसोई नहीं हैं। इस पर नाराज़गी जताते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग को अनटाइड फंड से एक करोड़ रुपये धनराशि जारी की। क्लेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा को लेकर जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्कूलों में खाना पकाने के लिए सिर्फ आयरन या स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल किए जाएं और एल्यूमीनियम बर्तनों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने बताया कि अधिक छात्र

संख्या वाले 50 स्कूलों में भोजन माता की एक अतिरिक्त सहायक महिला की तैनाती की जाएगी, जिससे भोजन व्यवस्था और भी बेहतर हो सके। इससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। गौरतलब है कि जिले में एक हजार 306 स्कूलों में पीएम पोषण योजना लागू है, जिससे करीब 70 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

संयुक्त समिति

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर केंद्र स्तर पर गठित संयुक्त संसदीय समिति उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर है। दौरे के पहले दिन समिति ने देहरादून में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव जाने। साथ ही समिति ने एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी और आरईसी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की और उनकी राय जानी। इससे पहले समिति के अध्यक्ष पी.पी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के साथ देश में एक साथ चुनाव पर विचार विमर्श किया। विधानसभा अध्यक्ष ने समिति को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समिति आज मुख्य सचिव के साथ ही गृह, वित्त, विधि, शिक्षा विभागों के प्रमुखों, पुलिस महानिदेशक के साथ चर्चा करेगी। इसके बाद बार काउंसिल के पदाधिकारियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, आईआईटी रूड़की के प्रतिनिधियों के साथ एक साथ चुनाव पर भी बात करेगी और उनके सुझाव लेगी। स्थानीय स्तर की प्रमुख हस्तियों के साथ चर्चा के लिए भी एक सत्र निर्धारित किया गया है।

समिति अपने अध्ययन दौरे के दूसरे व अंतिम दिन बृहस्पतिवार को सबसे पहले सुबह समिति उत्तराखंड के मुख्य सचिव के साथ ही गृह, वित्त, विधि, शिक्षा विभागों के प्रमुखों, पुलिस महानिदेशक के साथ चर्चा करेगी। दोपहर बाद, बॉर कौंसिल के पदाधिकारियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, आईआईटी रूड़की के प्रतिनिधियों के साथ एक साथ चुनाव पर बात करेगी और उनके सुझाव लेगी। स्थानीय स्तर की प्रमुख हस्तियों के साथ चर्चा के लिए भी एक सत्र निर्धारित किया गया है।

पीरूल उत्तरकाशी

उत्तरकाशी जिले में अपर यमुना वन प्रभाग की विभिन्न रेंजों में गठित वन पंचायतों के लिए अब पीरूल आय का जरिया बनेगा। विभाग ने पहली बार वन पंचायतों के माध्यम से दस रुपये प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदना शुरू कर दिया है। इससे जहां वनों में लगने वाली आग की घटनाओं पर रोक लगेगी, वहीं वन पंचायतों को आर्थिक लाभ भी होगा।

अपर यमुना वन प्रभाग की मुंगरशंति, नौगांव, कुथनौर और यमुनोत्री रेंज में बनाए गए कलेक्शन सेंटरों में इस वर्ष 20 हजार क्विंटल पीरूल एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक वन पंचायत को सिविल और आरक्षित वन क्षेत्र से 50 क्विंटल पीरूल एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है। अपर यमुना वन प्रभाग की इन रेंजों में 174 वन पंचायतें हैं।

पहले चरण में इन रेंजों की उन वन पंचायतों को पिरूल एकत्रीकरण की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें ढुलान करने में आसानी हो। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि अपेक्षित परिणाम आने पर अगले वर्ष प्रत्येक वन पंचायत को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा।

मुंगरशंति रेंज के वन क्षेत्राधिकारी शेखर राणा का कहना है कि मुंगरशंति और नौगांव रेंज से पिरूल एकत्रीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वन पंचायतों ने पिरूल पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। प्रत्येक वन पंचायत को 50 क्विंटल पिरूल का लक्ष्य दिया गया है।

गौरतलब है कि जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं का मुख्य कारण पीरूल माना गया है, जिससे प्रत्येक वर्ष वन संपदा और जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंचता है।

मॉनसून तैयारी बागेश्वर

बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा–निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश देते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी अपने मोबाइल फोन हर समय ऑन रखें और आपदा उपकरणों की जांच समय रहते कर ली जाएं। जिलाधिकारी ने तहसील और थाना स्तर पर उपकरणों के संचालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश भी दिए हैं।

गुलदार दहशत

उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के समीप कल शाम तेखला के समीप तीन गुलदारों के एक साथ दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुलदार तेखला में होटलों और भागीरथी नदी के किनारे दिखाई दिए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि एक–दो दिनों से गुलदार लगातार क्षेत्र में दिख रहे हैं। वहीं, तेखला के आस–पास होटल और आवासिय बस्ती होने के कारण यात्रियों और लोगों में भय का माहौल बना है। उन्होंने गुलदार की चहलकदमी और सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र में गश्त बढ़ाए जाने की वन विभाग से मांग की है।